



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, १९ अप्रैल, १९९७/२९ चैत्र, १९१९

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, १९ अप्रैल, १९९७

संख्या एल० एल० आर० (डी) (१६)-३४/९७-लेजिसलेशन. —हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २०० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तारीख १८-४-१९९७ को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, १९९७ (१९९७ का १) को १९९७ के हिमाचल प्रदेश अधिनियम

संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधिन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश, राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि)।

1997 का अधिनियम संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997

(राज्यपाल द्वारा तारीख 18 अप्रैल, 1997 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 है । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(2) यह 10 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

1994 का
12.

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 4 का संशोधन ।

“(3) नगर निगम में इस धारा के अधीन सीधे निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त, पूर्णतः या अंशतः नगरपालिका क्षेत्र में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सदस्य, भी पार्षद् होंगे और राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, पार्षद् के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन नामनिर्देशित व्यक्तियों को निगम की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।” ।

3. मूल अधिनियम की धारा 254 में, उप-धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 254 का संशोधन ।

“(5) जहां निर्माण का स्वामी अपने बन्द किए गए कार्य या उस द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के पश्चात् संशोधित रेखांक प्रस्तुत करता है और उसमें मंजूर रेखांक से विचलन है, तो आयुक्त, धारा 255 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष या साधारण निदेशों के अधीन विचलन के मामलों का मंजूर रेखांक से दस प्रतिशत तक प्रशमन कर सकेगा :

परन्तु जहां संशोधित रेखांक में—

(i) किसी सरकारी भूमि या नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि; या

(ii) किसी लोक सड़क, मार्ग, पथ या नाली को आच्छादित करते हुए ; या

(iii) हिमाचल प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1968 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, निर्माण का परिनिर्माण अन्तर्वर्तित है ;

1969 का

21

वहां आयुक्त मंजूर रेखांक से विचलन का प्रशमन नहीं करेगा ।

(5 क) उप-धारा (5) के अधीन आयुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, मण्डलायुक्त को अपील कर सकेगा ।

(5 ख) उप-धारा (5 क) के अधीन अपील में मण्डलायुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, मण्डलायुक्त द्वारा किए गए आदेश से तीस दिन के भीतर और ऐसी विहित रीति में, जैसी विहित की जाए, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा ।

(5 ग) अपील प्राधिकारी कारणों को अभिलिखित करते हुए, उप-धाराएं (5 क) और (5 ख) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के पश्चात् भी अपीलें दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा और उक्त उप-धाराओं के अधीन तीस दिन की अवधि की संगणना करने के लिए, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रतियां उपाप्त करने के लिए व्यतीत हुआ समय अपवर्जित किया जाएगा ।

(5 घ) राज्य सरकार उप-धाराएं (5), (5 क) और (5 ख) में किसी बात के होते हुए भी, अत्यधिक कठिनाई के असाधारण मामलों में मंजूर रेखांक से विचलन के मामलों का प्रशमन कर सकेगी ।” ।

1997 के
अध्यादेश
संख्यांक 1
का
निरसन ।

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 7 of 1997.

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) ACT, 1997**

(As Assented to by the Governor on 18th April, 1997)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994
(12 of 1994)*

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 1997.

Short title
and com-
mencement.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 10th day of January, 1997.

2. For sub-section (3) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amend-
ment of
section 4.

“(3) In the Corporation, in addition to persons chosen by direct election under this section, the Members of the State Legislative Assembly, representing constituencies which comprise wholly or partly in municipal area, shall also be the Councillors and the State Government may, by notification, also nominate as Councillors, not more than three, persons having special knowledge or experience of Municipal administration;

Provided that the persons nominated under this sub-section shall not have the right to vote in the meeting of the Corporation.”.

3. In section 254 of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

Amend-
ment of
section 254.

“(5) Where the owner of the building submits the revised plan, after the work has been stopped by him or the work is completed by him and there are deviations from the sanctioned plan, the Commissioner may, subject to the special or general directions of the State Government under section 255, compound the cases of deviations upto 10% from the sanctioned plan :

Provided that where the revised plan involves erection of building—

(i) on any Government land or the land vested in a municipality or a local authority ; or

(ii) by covering any public road, street, path or drain ; or

(iii) by contravening the provisions of the Himachal Pradesh Roadside Land Control Act, 1968 ;

21 of 1969

the Commissioner shall not compound deviations from the sanctioned plan.

(5 A) Any person aggrieved by the decision of the Commissioner under sub-section (5), may, within thirty days from the passing of the order by the Commissioner and in such manner as may be prescribed, appeal to the Divisional Commissioner.

(5 B) Any person aggrieved by the decision of the Divisional Commissioner in appeal under sub-section (5 A), may, within thirty days from the order made by the Divisional Commissioner and in such manner as may be prescribed, appeal to the State Government.

(5 C) The appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, allow the appeals to be filed after the expiry of the period of thirty days specified in sub-sections (5A) and (5 B) and for calculating the period of thirty days under the said sub-sections, the time spent in procuring the certified copies of the orders to be appealed against shall be excluded.

(5 D) Notwithstanding anything contained in sub-sections (5), (5 A) and (5 B), the State Government may, in exceptional cases of extreme hardship, compound the cases of deviations from sanctioned plans.”.

Repeal of
Ordinance
No. 1 of
1997.

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1997, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1997, anything done or action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of this Act.